

न्यायालय:-वाचस्पति मिश्र,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,बालाघाट
शृंखला न्यायालय-बैहर

सत्र प्रकरण क्रमांक-04 / 2017

फाईलिंग नंबर-48 / 2017

सी.एन.आर. नंबर-MP5005-000150-2017

संस्थित दिनांक-04.10.2016

म0प्र0 राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र-गढ़ी

तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

1- पंचम पिता आनंद सिंह मेरावी उम्र 23 वर्ष

2- बंटू उर्फ प्रमोद पिता मुन्नालाल उम्र 19 वर्ष

दोनों निवासी-ग्राम किडगीटोला थाना गढ़ी

तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - अभियुक्तगण।

=====

श्री अभिजीत बापट, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन।

श्री जी.आर. यादव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

=====

- / / / आदेश / / / -

(धारा 232 द.प्र.सं. के तहत आज दिनांक 15 मई 2018 को घोषित)

1. अभियुक्त पंचम के विरुद्ध धारा 341, 366, 376 (1), 506 भाग-दो भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 15.07.2016 को शाम 6:00 बजे ग्राम पांडूतला अंतर्गत थाना गढ़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 स्थित सरपंच ढाबा के पास लोकमार्ग पर अभियोक्त्री (जिसका नाम रेसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) का आटो क्रमांक एम.पी. 15 आर. 0876 को रोककर एवं उसकी यात्री अभियोक्त्री को अपहरण कर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने तथा आपराधिक अभित्रास

कारित करने का आरोप है एवं सह-अभियुक्त बंटू पर उक्त स्थान पर रास्ते में मोटरसायकल अड़ाकर ऑटो क्रमांक एम.पी. 51 आर. 0876 को रोककर सदोष अवरोध कारित करने का आरोप है।

2. अभियोजन मामला यह है कि घटना दिनांक 15.07.2016 की शाम अभियोक्त्री मजदूरी करके ऑटो क्रमांक एम.पी. 51 आर. 0876 से लौट रही थी तभी रास्ते में आरोपी पंचम एवं सह-अभियुक्त बंटू ने आटो रोक लिया तथा अभियोक्त्री को जबरदस्ती जंगल ले जाकर उसके साथ पंचम ने बलात्कार किया। घटना के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा दिनांक 16.07.2016 को प्रथम सूचना लेख कराई। थाना गढ़ी द्वारा अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाकर मेमोरण्डम लिया गया। सम्यक् विवेचना उपरांत अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कथन लेखबद्ध कराए गए, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपार्पण उपरांत इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

3. चार्ट के स्टेज पर अभियुक्तगण ने अपराध से अस्वीकार किया। अभियुक्त पंचम द्वारा यह बचाव लिया गया कि प्रस्तुत मामले में उसे झूठा आलिप्त किया गया तथा सह-अभियुक्त बंटू ने निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

अवधार्य प्रश्न यह है कि :-

1- क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.07.2016 को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर अभियोक्त्री के ऑटो क्रमांक एम.पी. 51 आर. 0876 को रोककर उसे गलत आशय से व्यपहरण कारित किया ?

2— क्या उक्त दिनांक को आरोपी पंचम ने अभियोक्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्थानीय जंगल ले जाकर बलात्कार किया ?

3— क्या उक्त दिनांक को सह-अभियुक्त बंटू ने उक्त ऑटो क्रमांक एम. पी. 51 आर. 0876 को आरोपी पंचम के साथ मिलकर ऑटो रोककर सड़ोष अवरोध कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक 1 से 3 का निष्कर्ष :-

4. लैंगिक अपराध के संबंध में सर्वप्रथम विक्टिम की हैसियत एवं साक्ष्य के संबंध में विधिक स्थिति की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत :- **गुरमीत सिंह** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। **न्यायदृष्टांत :- The State Of Punjab vs Gurmit Singh & Ors on 16 January, 1996**
Equivalent citations: 1996 AIR 1393, 1996 SCC (2) 384 .

The testimony of the victim in such cases is vital and unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty to act on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. Seeking corroboration of her statement before relying upon the same, as a rule, in such cases amounts to adding insult to injury. Why should the evidence of a girl or a woman who complains of rape or sexual molestation, be viewed with doubt, disbelief or suspicion? The Court while appreciating the evidence of a prosecutrix may look

for some assurance of her statement to satisfy its judicial conscience, since she is a witness who is interested in the outcome of the charge levelled by her, but there is no requirement of law to insist upon corroboration of her statement to base conviction of an accused. The evidence of a victim of sexual assault stands almost at par with the evidence of an injured witness and to an extent is even more reliable. Just as a witness who has sustained some injury in the occurrence, which is not found to be self inflicted, is considered to be a good witness in the sense that he is least likely to shield the real culprit, the evidence of a victim of a sexual offence is entitled to great weight, absence of corroboration notwithstanding. Corroborative evidence is not an imperative component of judicial credence in every case of rape. Corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under given circumstances. It must not be over-looked that a woman or a girl subjected to sexual assault is not an accomplice to the crime but is a victim of another persons's lust and it is improper and undesirable to test her evidence with a certain amount of suspicion, treating her as if she were an accomplice. Inferences have to be drawn from a given set of facts and circumstances with realistic diversity and not dead uniformity lest that type of rigidity in the shape of rule of law is

introduced through a new form of testimonial tyranny making justice a casualty. Courts cannot cling to a fossil formula and insist upon corroboration even if, taken as a whole, spoken of by the victim of sex crime strikes the judicial mind as probable. In State of Maharashtra Vs. Chandraprakash Kewalchand Jain (1990 (1) SCC 550) Ahmadi, J. (as the Lord Chief Justice then was) speaking for the Bench summarised the position in the following words:

"A prosecutrix of a sex offence cannot be put on par with an accomplice. She is in fact a victim of the crime. The Evidence Act nowhere says that her evidence cannot be accepted unless it is corroborated in material particulars. She is undoubtedly a competent witness under Section 118 and her evidence must receive the same weight as is attached to an injured in cases of physical violence. The same degree of care and caution must attach in the evaluation of her evidence as in the case of an injured complainant or witness and no more. What is necessary is that the court must be alive to and conscious of the fact that it is dealing with the evidence of a person who is interested in the outcome of the charge levelled by her. If the court keeps this in mind and feels satisfied that it can act on the evidence of the prosecutrix, there is no rule of law or practice incorporated in the Evidence Act similar to illustration .

(b) to Section 114 which requires it to look for corroboration. If for some reason the court is hesitant to place implicit reliance on the testimony of the prosecutrix it may look for evidence which may lend assurance to her testimony short of corroboration required in the case of an accomplice. The nature of evidence required to lend assurance to the testimony of the prosecutrix must necessarily depend on the facts and circumstances of each case. But if a prosecutrix is an adult and of full understanding the court is entitled to base a conviction on her evidence unless the same is shown to be infirm and not trustworthy. If the totality of the circumstances appearing on the record of the case disclose that the prosecutrix does not have a strong motive to falsely involve the person charged, the court should ordinarily have no hesitation in accepting her evidence."

5. अब यह देखना है कि क्या अभियोजन ने उक्त रेसियो के परिप्रेक्ष्य में आरोपी पंचम के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे स्थापित किया है।

6. अभियोक्त्री (अ.सा.4) ने उक्त आरोपीगण की पहचान संदेह से परे स्थापित किया है। अभियोक्त्री ने बयान में आगे यह बताया है कि उक्त घटना दिनांक को उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई न ही आरोपी पंचम ने बलात्कार किया और न ही उसके साथ शारीरिक संबंध (Sexual Inter Course) स्थापित किया था। अभियोक्त्री (अ.सा.4) ने आगे स्पष्ट किया है कि उसने स्थानीय ग्रामीणों के दबाव में आकर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेख कराई थी तत्पश्चात् पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था एवं अंडरगारमेंट चिकित्सक ने जप्त किया था।

7. अभियोजन ने अभियोक्त्री (अ.सा.4) को प्रतिकूल घोषित कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत परीक्षण किया है। साक्षी ने धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण किए जाने पर पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 5 के सारवान भाग को (Disown) अस्वीकार किया तथा पुलिस बयान प्र.पी. 6 के सारवान भाग को भी अस्वीकार किया है। जिरह में स्पष्ट किया है कि उसने स्थानीय ग्रामीणों के दबाव में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना संस्थित कराई थी। यह स्पष्ट किया है कि उसने मात्र प्रपत्रों पर पुलिस के कहने पर निशानी-अंगूठा लगाया था। इस प्रकार अभियोक्त्री के बयान में आरोपी के विरुद्ध फंसाने वाला तथ्य सामने नहीं आया है।

8. उक्त संबंध में मुन्नालाल (अ.सा.1), देवबतीबाई (अ.सा.2) अभिभावकगण ने अपने बयान में बताया है कि अभियोक्त्री ने घटना के संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं की थी। साक्षी ने मात्र अभियोक्त्री के मेडिकल परीक्षण हेतु सहमति पत्र प्र.पी. 2 पर फार्मल रूप से हस्ताक्षर करना, नक्शा मौका प्र.पी. 1 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन ने मुन्नालाल (अ.सा.1) एवं देवबतीबाई (अ.सा.2) को प्रतिकूल घोषित कर जिरह किया है। उक्त साक्षीगण ने अपने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 3, प्र.पी. 4 के सारवान भाग को अस्वीकार (Disown) किया है अर्थात् घटना के संबंध में अभियोक्त्री ने अपने अभिभावकगण को तत्काल कोई इस आशय की शिकायत नहीं की कि आरोपी पंचम ने उसके साथ बलात्कार की घटना कारित किया है।

9. प्रतिकूल घोषित साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा हेतु **रमेश मिश्रा किमिनल अपील** में पारित मत अवलोकनीय है, जिसमें यह मत प्रतिपादित

किया गया है कि प्रतिकूल घोषित साक्षी के बयान का प्रयोग उभयपक्ष द्वारा किया जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत :- " उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश मिश्रा " किमिनल अपील क्रमांक 884 वर्ष 1996 निर्णय दिनांक 13.8.96 अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

Held that it is equally settled law that the evidence of hostile witness would not be toally rejected, if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can be subject to closest scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted.

10. इसके विपरीत दीपक यादव (अ.सा.3) ने व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री उसकी साली है तथा वह रोपा लगाने गई थी, रास्ते में ऑटो से लौट रही थी तब उक्त आरोपीगण ने अभियोक्त्री को पकड़कर जंगल की तरफ ले गये बाद में उसके साथ क्या हुआ जानकारी नहीं है। यह स्पष्ट किया है कि बाद में 02:30 बजे रात्रि में अभियोक्त्री आरोपीगण से बचकर घर आयी थी तब उसने परिवार के सदस्यों को आरोपीगण द्वारा बलात्कार करना बताया था लेकिन साक्षी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उसने घटना के संबंध में अभियोक्त्री के बताए अनुसार बयान दिया है। यह स्पष्ट किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। चूंकि मुख्य (Star) साक्षी अभियोक्त्री ने अभियोजन मामले का अनुसमर्थन नहीं किया है। अतः दीपक यादव (अ.सा.3) की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

11. उक्त संबंध में डॉ. रश्मि वाघमारे (अ.सा.8) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 18.07.2016 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ रहने हुए थाना

गढ़ी द्वारा अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु लाए जाने पर, परीक्षण किये जाने पर अभियोक्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित पाया था। शरीर के बाह्य भाग पर एवं प्रायवेट पार्ट पर कोई इंजूरी नहीं पायी थी, पेट नर्म था। डॉ. वाघमारे (अ.सा.8) ने अभियोक्त्री के आंतरिक परीक्षण करने पर हाईमन फटा नहीं पाया था, उंगली का ऊपरी सिरा वैजाईना में जा सकता था। अभियोक्त्री की वैजाईनल स्लाईड तैयार कर, अंडरवियर सीलबंद कर प्र.पी. 15 की परीक्षण रिपोर्ट जारी की थी जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं अर्थात् मेडिकल साक्षी के बयान में यह नहीं आया है कि अभियोक्त्री का हाईमन रैचर था अथवा बलात्कार के संबंध में कोई निश्चायक राय या ओपिनियन प्रकट नहीं किया है।

12. डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.7) ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 08.08.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ रहते हुए थाना गढ़ी के आरक्षक द्वारा आरोपी पंचम को परीक्षण हेतु लाए जाने पर अभियुक्त को संभोग हेतु सक्षम पाया था, अभियुक्त के आंतरिक व बाहरी भाग पर कोई इंजूरी नहीं थी। अभियुक्त की सीमन स्लाईड तैयार कर प्र.पी. 14 की परीक्षण रिपोर्ट जारी की थी जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त चिकित्सक साक्षियों के बयान के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

13. क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल की रिपोर्ट प्र.पी. 19 में भी अभियोक्त्री की वैजाईना में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया न ही उसकी अंडरगारमेंट में वीर्य के धब्बे पाये गये अर्थात् रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट से भी बलात्कार किए जाने का तथ्य संभाव्य होना नहीं पाया जाता है।

14. विवेचक नीलेश परतेती (अ.सा.9) विवेचना को फार्मल रूप से प्रमाणित किया है उन्होंने अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु मुलाहिजा

आवेदन प्र.पी. 15—ए भरकर जिला चिकित्सालय भेजकर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना, घटनास्थल जाकर मौकानक्शा प्र.पी. 7 निर्मित किया जाना, साक्षियों के बयान अभिलिखित किया जाना, अभियोक्त्री के कथन की विडियोग्राफी कराया जाना तथा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाना व्यक्त किया है।

15. विवेचक नीलेश परतेती ने आगे व्यक्त किया है कि उन्होंने आरोपी पंचम से अपराध में प्रयुक्त मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 07 ई. 1678 को मेमोरेण्डम प्र.पी. 10 निर्मित कर जप्ती पत्र प्र.पी. 11 के माध्यम से जप्त किया जाना, आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 12, प्र.पी. 13 निर्मित किया था तथा साक्षी ने आगे आरोपी पंचम का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त किया है। साक्षी ने आगे व्यक्त किया है कि हॉस्पिटल से अभियोक्त्री की वैजाईना, अंडरवियर, आरोपी की सीमन स्लाईड क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा था अर्थात् रासायनिक परीक्षण के आधार पर प्र.पी. 20 प्राप्त किया था। उक्त साक्षी के बयान के आधार पर भी अभियोजन को कोई विशेष बल नहीं मिलता है।

16. पटवारी रणजीत सिंह सैयाम (अ.सा.5) ने बताया है कि तहसीलदार के निर्देश पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी. 1 निर्मित किया था। इसी प्रकार टंकनदास सोनवानी (अ.सा.6) मेमोरेण्डम के फार्मल साक्षी है। मेमोरेण्डम प्र.पी. 10, जप्ती पत्र प्र.पी. 11 एवं गिरफ्तारी पत्र प्र.पी. 12 तथा प्र. पी. 13 के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किया जाना प्रमाणित किया है। अभियोजन ने साक्षी को प्रतिकूल घोषित कर जिरह किया है अर्थात् टंकनदास सोनवानी द्वारा मेमोरेण्डम दिनांक को आरोपी पंचम के कब्जे से मोटरसायकल की जप्ती एवं बरामदगी के तथ्य का अनुसमर्थन नहीं किया है।

17. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष गुरमीत सिंह के मामले में वर्णित रिसियो के अनुसार आरोपी पंचम एवं सह-अभियुक्त बंटू उर्फ प्रमोद के विरुद्ध अपना मामला संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है। परिणामतः संदेह का लाभ देते हुए आरोपी पंचम को धारा 341, 366, 376 (1), 506 भाग-दो भा.द.वि. एवं आरोपी बंटू उर्फ प्रमोद को धारा 341 भा.द.वि. के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

19. मामले में जप्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक : 15 मई 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित।

सही / -

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर